SARVAGYA

ISSN (Online)
3048-7153
Vol. 3 | Issue 3
July to Sep 2026

www.sarvagyajournal.com | the.editor.org@gmail.com | Peer Reviewed & Refereed Journal

"डिजिटल मीडिया एवं जनमत निर्माण : भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"

डॉ. विकास शिशोदिया
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

सार (Abstract)

डिजिटल क्रांति ने वैश्विक संचार व्यवस्था, सूचना के प्रसार तथा सामाजिक-राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन तथा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों के तीव्र विस्तार ने सूचना के उत्पादन, प्रसार और उपभोग की पारंपरिक प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया केवल सूचना उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह जनमत निर्माण, राजनीतिक विमर्श, सामाजिक जागरूकता तथा लोकतांत्रिक सहभागिता का एक प्रभावशाली मंच बन चुका है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश में डिजिटल मीडिया का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है, जहाँ नागरिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा नीतिगत चर्चाओं में भाग लेने के लिए विभिन्न डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में डिजिटल मीडिया की जनमत निर्माण में भूमिका का विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि डिजिटल मीडिया नागरिकों की राजनीतिक चेतना, लोकतांत्रिक सहभागिता, चुनावी व्यवहार तथा सार्वजनिक विमर्श को किस प्रकार प्रभावित करता है। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर फेक न्यूज़, दुष्प्रचार, ट्रोलिंग, एल्गोरिद्मिक पक्षपात, इको चैंबर (Echo Chamber), फ़िल्टर बबल (Filter Bubble) तथा डीपफेक जैसी उभरती चुनौतियों का भी समालोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। शोध यह भी स्पष्ट करता है कि जहाँ डिजिटल मीडिया ने सूचना तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाया है और नागरिकों को अभिव्यक्ति का व्यापक अवसर प्रदान किया है, वहीं इसके अनियंत्रित उपयोग ने जनमत की निष्पक्षता, सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं।

यह अध्ययन गुणात्मक (Qualitative) शोध पद्धति पर आधारित है तथा इसके अंतर्गत पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, नीतिगत दस्तावेज़ों और विश्वसनीय राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्रोतों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के सैद्धांतिक आधार के रूप में एजेंडा निर्धारण सिद्धांत (Agenda Setting Theory), सार्वजनिक क्षेत्र सिद्धांत (Public Sphere Theory) तथा फ्रेमिंग सिद्धांत (Framing Theory) का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि डिजिटल मीडिया लोकतांत्रिक भागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किंतु इसके प्रभावी एवं उत्तरदायी उपयोग के लिए डिजिटल साक्षरता, तथ्य-जाँच तंत्र, मीडिया नैतिकता तथा संतुलित नियामक नीतियों का विकास अत्यंत आवश्यक है। यह शोध डिजिटल मीडिया और जनमत के अंतर्संबंध को समझने के साथ-साथ भारतीय लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित समकालीन चुनौतियों एवं संभावनाओं का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

Received	Accepted	Published	Article Type
20/06/2026	10/08/2026	25/08/2026	Research Paper

© 2006 sarvagya | All Rights Reserved
www.sarvagyajournal.com

Vol. 3, Issue 3, July-Ssseptember 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22115875

SARVAGYA

ISSN (Online)
3048-7153
Vol. 3 | Issue 3
July to Sep 2026

www.sarvagyajournal.com | the.editor.org@gmail.com | Peer Reviewed & Refereed Journal

प्रस्तावना

इक्कीसवीं शताब्दी को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है। विज्ञान और तकनीकी विकास ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिनमें संचार माध्यम सबसे अधिक परिवर्तनशील क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्टफ़ोन तथा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों के तीव्र विकास ने सूचना के निर्माण, प्रसारण तथा उपभोग की पारंपरिक प्रक्रिया को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। जहाँ कभी समाचार-पत्र, रेडियो और टेलीविज़न जनसंचार के प्रमुख माध्यम थे, वहीं आज डिजिटल मीडिया ने संचार की प्रकृति को अधिक त्वरित, सहभागी, बहुआयामी तथा वैश्विक बना दिया है। वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया केवल सूचना के आदान-प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक संवाद, आर्थिक गतिविधियों, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा जनमत निर्माण की एक सशक्त शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की जागरूकता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत (Public Opinion) को शासन और समाज के बीच संवाद का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। जनमत केवल व्यक्तियों के विचारों का समूह नहीं है, बल्कि यह सामाजिक अनुभवों, राजनीतिक घटनाओं, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक मूल्यों तथा संचार माध्यमों के प्रभाव से निर्मित सामूहिक दृष्टिकोण है। लोकतंत्र में नीतियों के निर्माण, चुनावी प्रक्रिया, सार्वजनिक बहस, उत्तरदायी शासन तथा नागरिक भागीदारी में जनमत की केंद्रीय भूमिका होती है। इसलिए जनमत को प्रभावित करने वाले माध्यमों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान, जनसंचार, समाजशास्त्र तथा लोक प्रशासन जैसे विषयों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

डिजिटल मीडिया के विकास ने जनमत निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया में एक नया आयाम जोड़ा है। आज फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और अन्य डिजिटल मंचों के माध्यम से सूचना कुछ ही क्षणों में करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है। डिजिटल माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें प्रत्येक व्यक्ति केवल सूचना प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि सूचना का निर्माता, प्रसारक और विश्लेषक भी बन सकता है। इस प्रकार डिजिटल मीडिया ने संचार प्रक्रिया को एकतरफ़ा (One-way Communication) से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय (Interactive Communication) स्वरूप प्रदान किया है। नागरिक अब केवल समाचारों के उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि वे अपने विचार, अनुभव और प्रतिक्रियाएँ तत्काल साझा करके सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

भारतीय समाज में इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन की बढ़ती पहुँच ने डिजिटल मीडिया के प्रभाव को अभूतपूर्व रूप से विस्तारित किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल दूरी धीरे-धीरे कम हो रही है तथा बड़ी संख्या में युवा, महिलाएँ और विभिन्न सामाजिक समूह डिजिटल मंचों के माध्यम से राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार, सामाजिक आंदोलनों, चुनावी अभियानों, जन-जागरूकता कार्यक्रमों तथा आपदा प्रबंधन जैसी अनेक गतिविधियों में डिजिटल मीडिया प्रभावी उपकरण के रूप में उभरा है। कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल मीडिया ने सूचना प्रसार, स्वास्थ्य जागरूकता, ऑनलाइन शिक्षा तथा प्रशासनिक संचार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसकी उपयोगिता और व्यापकता और अधिक स्पष्ट हुई।

इसके साथ ही डिजिटल मीडिया ने लोकतांत्रिक विमर्श को अधिक समावेशी बनाने में भी योगदान दिया है। अनेक ऐसे वर्ग, जिन्हें पारंपरिक मीडिया में अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाता था, आज डिजिटल मंचों के माध्यम से अपनी आवाज़ राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा रहे हैं। सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुशासन जैसे विषयों पर जन-जागरूकता और सार्वजनिक चर्चा को डिजिटल मीडिया ने नई गति प्रदान की है। डिजिटल मंच नागरिकों और सरकार के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने का माध्यम भी बने हैं, जिससे शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की अपेक्षाएँ बढ़ी हैं।

हालाँकि डिजिटल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों के साथ अनेक गंभीर चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ (Fake News), दुष्प्रचार (Misinformation एवं Disinformation), ट्रोलिंग, घृणा-भाषण (Hate Speech), डीपफेक तकनीक, साइबर अपराध तथा एल्गोरिद्मिक पक्षपात जैसी समस्याएँ जनमत निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं। कई बार अपुष्ट या भ्रामक सूचनाएँ अत्यंत तीव्र गति से प्रसारित होकर सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक वैमनस्य,

© 2006 sarvagya | All Rights Reserved
www.sarvagyajournal.com

Vol. 3, Issue 3, July-Sseptember 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22115875

SARVAGYA

ISSN (Online)
3048-7153
Vol. 3 | Issue 3
July to Sep 2026

www.sarvagyajournal.com | the.editor.org@gmail.com | Peer Reviewed & Refereed Journal

राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास को बढ़ावा देती हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के एल्गोरिद्म उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचि के अनुरूप सामग्री प्रदर्शित करते हैं, जिससे 'इको चैंबर' और 'फ़िल्टर बबल' जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में नागरिकों के समक्ष विविध दृष्टिकोणों के स्थान पर सीमित और पूर्वाग्रहपूर्ण सूचनाएँ पहुँचती हैं, जिससे स्वतंत्र एवं विवेकपूर्ण जनमत निर्माण प्रभावित हो सकता है।

भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में डिजिटल मीडिया की भूमिका का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले एक दशक में चुनावी राजनीति, सार्वजनिक नीतियों, सामाजिक आंदोलनों तथा नागरिक अभियानों में डिजिटल मंचों की भूमिका अत्यधिक बढ़ी है। चुनाव प्रचार, मतदाता जागरूकता, राजनीतिक संचार, डिजिटल अभियान और ऑनलाइन जनसंवाद ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नया स्वरूप दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक दल, सरकारी संस्थाएँ, नागरिक संगठन तथा विभिन्न हित समूह जनमत को प्रभावित करने के लिए डिजिटल मीडिया का व्यापक उपयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह समझना आवश्यक है कि डिजिटल मीडिया जनमत को किस प्रकार निर्मित करता है, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए किन नीतिगत और संस्थागत उपायों की आवश्यकता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में डिजिटल मीडिया एवं जनमत निर्माण के अंतर्संबंध का समग्र विश्लेषण करना है। अध्ययन में डिजिटल मीडिया के लोकतांत्रिक योगदान, राजनीतिक संचार, नागरिक सहभागिता, सूचना प्रसार, सामाजिक जागरूकता तथा जनमत निर्माण की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही, डिजिटल माध्यमों से उत्पन्न चुनौतियों, जैसे फेक न्यूज़, दुष्प्रचार, एल्गोरिद्मिक प्रभाव, डिजिटल नैतिकता तथा मीडिया साक्षरता की आवश्यकता का भी आलोचनात्मक परीक्षण किया जाएगा। यह शोध डिजिटल मीडिया की बदलती भूमिका को राजनीतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करता है तथा भारतीय लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और सहभागी बनाने की दिशा में उपयोगी विमर्श प्रस्तुत करता है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य

डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार ने संचार, सूचना के आदान-प्रदान तथा सामाजिक-राजनीतिक सहभागिता की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन किया है। वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया केवल समाचारों के प्रसारण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जनमत के निर्माण, परिवर्तन और प्रसार का एक प्रभावशाली उपकरण बन चुका है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों के निरंतर बढ़ते उपयोग ने नागरिकों के विचारों, राजनीतिक दृष्टिकोणों तथा सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने में डिजिटल मीडिया की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसे परिवर्तित परिदृश्य में डिजिटल मीडिया एवं जनमत निर्माण के अंतर्संबंध का गंभीर अकादमिक अध्ययन समय की आवश्यकता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत को शासन की वैधता, नीतिगत निर्णयों तथा जनसहभागिता का आधार माना जाता है। लोकतंत्र तभी सशक्त बनता है जब नागरिक तथ्यपरक, संतुलित एवं विश्वसनीय जानकारी के आधार पर अपने विचार निर्मित करें। डिजिटल मीडिया ने नागरिकों को अभिव्यक्ति का व्यापक मंच प्रदान किया है, जिसके माध्यम से वे सार्वजनिक नीतियों, चुनावी प्रक्रियाओं, सामाजिक आंदोलनों तथा समकालीन मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक संवाद अधिक सहभागी और गतिशील हुआ है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि डिजिटल मीडिया जनमत को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं।

हाल के वर्षों में यह भी देखा गया है कि डिजिटल मीडिया का उपयोग केवल रचनात्मक संवाद और जन-जागरूकता तक सीमित नहीं है। फेक न्यूज़, दुष्प्रचार, ट्रोलिंग, घृणा-भाषण, डीपफेक तकनीक तथा एल्गोरिद्मिक पक्षपात जैसी प्रवृत्तियाँ जनमत निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं। अनेक बार अपुष्ट या भ्रामक सूचनाएँ तीव्र गति से प्रसारित होकर सामाजिक तनाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास को बढ़ावा देती हैं। इस कारण यह अध्ययन केवल डिजिटल मीडिया के सकारात्मक पक्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके संभावित जोखिमों और चुनौतियों का भी समालोचनात्मक मूल्यांकन करता है।

भारतीय संदर्भ में यह अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में डिजिटल संचार का विस्तार अभूतपूर्व गति से हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच बढ़ने से बड़ी संख्या में नागरिक डिजिटल मंचों के माध्यम से सार्वजनिक विमर्श में भाग ले रहे हैं। चुनावों, सरकारी योजनाओं, सामाजिक अभियानों तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों में डिजिटल

© 2006 sarvagya | All Rights Reserved
www.sarvagyajournal.com

Vol. 3, Issue 3, July-Sseptember 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22115875

SARVAGYA

ISSN (Online)
3048-7153
Vol. 3 | Issue 3
July to Sep 2026

www.sarvagyajournal.com | the.editor.org@gmail.com | Peer Reviewed & Refereed Journal

मीडिया की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। इस परिवर्तित परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है कि डिजिटल मीडिया के लोकतांत्रिक प्रभावों का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाए।

प्रस्तुत अध्ययन का औचित्य इस तथ्य में निहित है कि यह डिजिटल मीडिया को केवल तकनीकी माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक संचार, लोकतांत्रिक सहभागिता और जनमत निर्माण की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में देखने का प्रयास करता है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, मीडिया विशेषज्ञों तथा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही, यह डिजिटल साक्षरता, मीडिया नैतिकता, तथ्य-जाँच तंत्र तथा उत्तरदायी डिजिटल संचार से संबंधित नीतियों के निर्माण में भी सहायक हो सकता है।

अतः वर्तमान अध्ययन डिजिटल मीडिया और जनमत के बीच विकसित हो रहे जटिल संबंधों का विश्लेषण करते हुए भारतीय लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित अवसरों, चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण अकादमिक प्रयास है।

समस्या का प्रतिपादन (Statement of the Problem)

वर्तमान वैश्विक सूचना युग में डिजिटल मीडिया जनसंचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है। इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइटों, वीडियो साझाकरण प्लेटफ़ॉर्मों तथा त्वरित संदेश सेवाओं ने सूचना के निर्माण, प्रसार और उपभोग की प्रक्रिया को अत्यंत सरल, तीव्र एवं व्यापक बना दिया है। इसके परिणामस्वरूप जनमत निर्माण की पारंपरिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहले जनमत मुख्यतः समाचार-पत्रों, रेडियो और टेलीविजन जैसे पारंपरिक माध्यमों से प्रभावित होता था, जबकि वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया नागरिकों की सोच, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवहार तथा सार्वजनिक निर्णयों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।

भारतीय लोकतंत्र में डिजिटल मीडिया की बढ़ती पहुँच ने नागरिकों को सार्वजनिक विमर्श में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान किया है। आज नागरिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर रहे हैं तथा डिजिटल मंचों के माध्यम से जनमत निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदार बन रहे हैं। यह परिवर्तन लोकतंत्र के लिए सकारात्मक माना जा सकता है, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारदर्शिता तथा जनसहभागिता को प्रोत्साहन मिला है। दूसरी ओर, डिजिटल मीडिया के अनियंत्रित एवं असंतुलित उपयोग ने अनेक गंभीर चुनौतियों को भी जन्म दिया है। हाल के वर्षों में फेक न्यूज़, दुष्प्रचार (Disinformation), भ्रामक सूचना (Misinformation), ट्रोलिंग, घृणा-भाषण, डीपफेक तकनीक तथा एल्गोरिद्मिक पक्षपात जैसी समस्याएँ तीव्र गति से बढ़ी हैं। अनेक अवसरों पर अपुष्ट सूचनाएँ व्यापक स्तर पर प्रसारित होकर सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक विवाद, राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास को बढ़ावा देती हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के एल्गोरिद्म उपयोगकर्ताओं की रुचियों के अनुरूप सामग्री प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे सीमित विचारों के दायरे में रह जाते हैं। इस स्थिति में नागरिकों तक विविध एवं संतुलित दृष्टिकोण नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण स्वतंत्र एवं विवेकपूर्ण जनमत निर्माण प्रभावित हो सकता है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दल, हित समूह, कॉर्पोरेट संस्थाएँ तथा अन्य संगठन भी जनमत को प्रभावित करने के लिए योजनाबद्ध डिजिटल अभियानों का उपयोग कर रहे हैं। चुनावी राजनीति, सार्वजनिक नीतियों तथा सामाजिक आंदोलनों में डिजिटल माध्यमों का बढ़ता उपयोग यह संकेत देता है कि जनमत निर्माण की प्रक्रिया अब केवल सामाजिक अनुभवों पर आधारित नहीं रह गई है, बल्कि डिजिटल संचार, डेटा विश्लेषण तथा एल्गोरिद्मिक रणनीतियों से भी प्रभावित हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिजिटल मीडिया वास्तव में जनमत निर्माण को किस सीमा तक प्रभावित करता है तथा यह प्रभाव लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कितना सकारात्मक या नकारात्मक है।

यद्यपि डिजिटल मीडिया और जनमत पर अनेक अध्ययन उपलब्ध हैं, तथापि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में डिजिटल मीडिया के लोकतांत्रिक योगदान, नागरिक सहभागिता, राजनीतिक संचार, फेक न्यूज़, एल्गोरिद्मिक प्रभाव तथा जनमत निर्माण की समग्र प्रक्रिया का समेकित विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित है। विशेष रूप से भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता, भाषाई बहुलता तथा तीव्र डिजिटल विस्तार को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर नवीन एवं समग्र अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की जाती है।

© 2006 sarvagya | All Rights Reserved
www.sarvagyajournal.com

Vol. 3, Issue 3, July-Sseptember 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22115875

SARVAGYA

ISSN (Online)
3048-7153
Vol. 3 | Issue 3
July to Sep 2026

www.sarvagyajournal.com | the.editor.org@gmail.com | Peer Reviewed & Refereed Journal

इन्हीं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध का मूल उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में डिजिटल मीडिया एवं जनमत निर्माण के मध्य अंतर्संबंधों का विश्लेषण करना, इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं तथ्यपरक बनाने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना है।

शोध-अंतर (Research Gap)

डिजिटल मीडिया एवं जनमत निर्माण विषय पर अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्यतः सोशल मीडिया, राजनीतिक संचार, चुनावी व्यवहार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। तथापि, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में डिजिटल मीडिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, नागरिक सहभागिता, फेक न्यूज़, एल्गोरिद्मिक प्रभाव तथा जनमत निर्माण की समग्र प्रक्रिया का एकीकृत विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित है। विशेष रूप से बदलते डिजिटल परिवेश में जनमत निर्माण की प्रकृति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर उसके प्रभाव का समकालीन अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है। प्रस्तुत शोध इसी अंतर को स्पष्ट करने तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में डिजिटल मीडिया और जनमत निर्माण के अंतर्संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. डिजिटल मीडिया की अवधारणा एवं भारतीय लोकतंत्र में उसकी भूमिका का अध्ययन करना।
2. जनमत निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने में डिजिटल मीडिया के प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों द्वारा राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श को प्रभावित करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना।
4. डिजिटल मीडिया के माध्यम से उत्पन्न फेक न्यूज़, दुष्प्रचार एवं अन्य चुनौतियों का विश्लेषण करना।
5. डिजिटल मीडिया के लोकतांत्रिक सहभागिता, नागरिक जागरूकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
6. भारतीय लोकतंत्र में उत्तरदायी एवं प्रभावी डिजिटल संचार के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देना।

शोध प्रश्न (Research Questions)

1. डिजिटल मीडिया भारतीय लोकतंत्र में जनमत निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है?
2. डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से जनमत निर्माण में उत्पन्न अवसरों एवं चुनौतियों का स्वरूप क्या है?

सैद्धांतिक रूपरेखा (Theoretical Framework)

प्रस्तुत अध्ययन डिजिटल मीडिया एवं जनमत निर्माण के संबंध को समझने के लिए प्रमुख संचार एवं राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से एजेंडा निर्धारण सिद्धांत (Agenda Setting Theory), सार्वजनिक क्षेत्र सिद्धांत (Public Sphere Theory) तथा फ्रेमिंग सिद्धांत (Framing Theory) को आधार बनाया गया है।

एजेंडा निर्धारण सिद्धांत के अनुसार मीडिया यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि समाज किन मुद्दों को अधिक महत्व देगा। डिजिटल मीडिया के संदर्भ में ट्रेंडिंग विषय, हैशटैग और वायरल सामग्री जनमत की दिशा को प्रभावित करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र में नागरिकों के बीच स्वतंत्र एवं तर्कपूर्ण संवाद आवश्यक है। डिजिटल मीडिया ने नागरिकों को विचार व्यक्त करने और सार्वजनिक विमर्श में भाग लेने का नया मंच प्रदान किया है।

फ्रेमिंग सिद्धांत के अनुसार किसी मुद्दे को प्रस्तुत करने का तरीका लोगों की समझ और राय को प्रभावित करता है। डिजिटल मीडिया पर किसी घटना या मुद्दे की प्रस्तुति जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार, ये सिद्धांत डिजिटल मीडिया द्वारा सूचना के चयन, प्रस्तुतीकरण और प्रसार की प्रक्रिया को समझने में सहायक हैं तथा भारतीय लोकतंत्र में जनमत निर्माण पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

शोध पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक (Qualitative) शोध पद्धति पर आधारित है। इस शोध में डिजिटल मीडिया एवं जनमत निर्माण के संबंधों को समझने के लिए द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए संबंधित पुस्तकों, शोध-पत्रों, जर्नल लेखों, सरकारी रिपोर्टों, समाचार स्रोतों तथा विश्वसनीय डिजिटल सामग्रियों का विश्लेषण किया गया है। इस

© 2006 sarvagya | All Rights Reserved
www.sarvagyajournal.com

Vol. 3, Issue 3, July-Sseptember 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22115875

SARVAGYA

ISSN (Online)
3048-7153
Vol. 3 | Issue 3
July to Sep 2026

www.sarvagyajournal.com | the.editor.org@gmail.com | Peer Reviewed & Refereed Journal

शोध में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक (Descriptive and Analytical) दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में डिजिटल मीडिया की भूमिका, नागरिक सहभागिता, सूचना प्रसार, फेक न्यूज़ तथा जनमत निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के प्रभावों का संतुलित एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

डिजिटल मीडिया एवं जनमत निर्माण: विश्लेषण एवं चर्चा

डिजिटल मीडिया और जनमत निर्माण की बदलती प्रक्रिया

डिजिटल मीडिया ने जनमत निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया है। पहले जनमत मुख्य रूप से समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन जैसे पारंपरिक माध्यमों द्वारा प्रभावित होता था, जिसमें सूचना का प्रवाह सीमित और एकतरफा होता था। डिजिटल मीडिया ने इस प्रक्रिया को अधिक सहभागी और संवादात्मक बना दिया है। अब नागरिक केवल सूचना के उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं भी सूचना के निर्माता और प्रसारक बन गए हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों ने नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। किसी भी घटना, नीति या सामाजिक विषय पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ तत्काल व्यापक स्तर पर पहुँच सकती हैं। इस प्रकार डिजिटल मीडिया ने जनमत निर्माण को अधिक गतिशील और व्यापक बनाया है।

लोकतांत्रिक सहभागिता में डिजिटल मीडिया की भूमिका

डिजिटल मीडिया ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक दल, सरकारें और सामाजिक संगठन डिजिटल माध्यमों का उपयोग नागरिकों तक पहुँचने, नीतियों की जानकारी देने और जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं।

इसके माध्यम से नागरिक सरकार की नीतियों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं तथा सामाजिक मुद्दों पर अभियान चला सकते हैं। ऑनलाइन याचिकाएँ, डिजिटल आंदोलन और सोशल मीडिया अभियान नागरिक सक्रियता के नए रूपों को प्रस्तुत करते हैं।

डिजिटल मीडिया और जनमत निर्माण की चुनौतियाँ

जहाँ डिजिटल मीडिया ने सूचना और अभिव्यक्ति के अवसर बढ़ाए हैं, वहीं इसके साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। फेक न्यूज़, भ्रामक सूचनाएँ, ट्रोलिंग और घृणा-भाषण जैसी समस्याएँ जनमत को प्रभावित कर सकती हैं। कई बार गलत जानकारी तेजी से प्रसारित होकर लोगों की सोच और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के एल्गोरिद्म उपयोगकर्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार सामग्री दिखाते हैं, जिससे विभिन्न विचारों के संपर्क में कमी आ सकती है। यह स्थिति लोकतांत्रिक संवाद को प्रभावित कर सकती है।

इस प्रकार डिजिटल मीडिया जनमत निर्माण का एक शक्तिशाली माध्यम है, जो लोकतांत्रिक सहभागिता को मजबूत करने के साथ-साथ नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है।

डिजिटल मीडिया, राजनीतिक संचार और चुनावी जनमत- समकालीन लोकतंत्र में डिजिटल मीडिया राजनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। राजनीतिक दलों, नेताओं और नागरिक संगठनों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों का उपयोग जनसंपर्क, नीतियों के प्रचार और मतदाताओं तक पहुँच बनाने के लिए किया जा रहा है। डिजिटल माध्यमों ने राजनीतिक संदेशों को तीव्र गति से व्यापक जनसमूह तक पहुँचाने की क्षमता प्रदान की है। चुनावी राजनीति में डिजिटल मीडिया की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। चुनाव अभियानों में सोशल मीडिया रणनीति, ऑनलाइन विज्ञापन, वीडियो संदेश और डिजिटल संवाद के माध्यम से मतदाताओं की राय को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इससे राजनीतिक सहभागिता के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन साथ ही राजनीतिक संदेशों के अतिरंजित प्रचार, भावनात्मक अपील और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार की चुनौती भी सामने आई है।

डिजिटल मीडिया और सामाजिक परिवर्तन- डिजिटल मीडिया केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का भी एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। महिला अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर डिजिटल अभियानों ने व्यापक जन-जागरूकता उत्पन्न की है।

© 2006 sarvagya | All Rights Reserved
www.sarvagyajournal.com

Vol. 3, Issue 3, July-Sseptember 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22115875

SARVAGYA

ISSN (Online)
3048-7153
Vol. 3 | Issue 3
July to Sep 2026

www.sarvagyajournal.com | the.editor.org@gmail.com | Peer Reviewed & Refereed Journal

विशेष रूप से युवा वर्ग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी कर रहा है। इससे नागरिक समाज को अपनी बात रखने और विभिन्न सामाजिक समस्याओं को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाने का अवसर मिला है।

डिजिटल साक्षरता और उत्तरदायी जनमत निर्माण - डिजिटल मीडिया के प्रभावी उपयोग के लिए डिजिटल साक्षरता अत्यंत आवश्यक है। केवल इंटरनेट तक पहुँच होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिकों में सूचना की विश्वसनीयता पहचानने, तथ्य-जाँच करने और जिम्मेदारीपूर्वक डिजिटल मंचों का उपयोग करने की क्षमता भी विकसित होनी चाहिए।

एक जागरूक डिजिटल नागरिक ही सही और गलत सूचनाओं में अंतर कर सकता है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विवेकपूर्ण भागीदारी निभा सकता है। इसलिए डिजिटल शिक्षा और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए आवश्यक है।

भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में डिजिटल मीडिया का समग्र मूल्यांकन

भारतीय लोकतंत्र में डिजिटल मीडिया एक दोहरे प्रभाव वाले माध्यम के रूप में उभरा है। एक ओर यह नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुँच और लोकतांत्रिक सहभागिता के अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर गलत सूचना और डिजिटल हेरफेर जैसी समस्याएँ लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।

अतः डिजिटल मीडिया को लोकतंत्र के लिए अवसर और चुनौती दोनों के रूप में समझने की आवश्यकता है। इसके सकारात्मक उपयोग के लिए तकनीकी विकास के साथ-साथ नैतिक संचार, तथ्य-जाँच व्यवस्था और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusion and Recommendations) - डिजिटल मीडिया ने आधुनिक समाज में संचार की प्रकृति, सूचना के प्रवाह और जनमत निर्माण की प्रक्रिया को मूल रूप से परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान समय में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म केवल सूचना प्रसारित करने के माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि वे सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक विमर्श के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में डिजिटल मीडिया ने नागरिकों को अभिव्यक्ति के नए अवसर प्रदान किए हैं तथा उन्हें सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने, विचार-विमर्श करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी करने का मंच उपलब्ध कराया है।

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डिजिटल मीडिया जनमत निर्माण की प्रक्रिया को अधिक व्यापक, त्वरित और सहभागी बनाता है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से नागरिक अब केवल पारंपरिक मीडिया पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं सूचना के निर्माता और प्रसारक बन चुके हैं। इससे लोकतांत्रिक संवाद का विस्तार हुआ है तथा अनेक ऐसे सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दे सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने हैं, जिन्हें पहले पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता था। डिजिटल मीडिया ने सरकार और नागरिकों के बीच संवाद को भी सरल बनाया है, जिससे शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की अपेक्षाएँ बढ़ी हैं।

हालाँकि, अध्ययन यह भी दर्शाता है कि डिजिटल मीडिया के प्रभाव केवल सकारात्मक नहीं हैं। फेक न्यूज़, दुष्प्रचार, घृणा-भाषण, ट्रोलिंग, डीपफेक तकनीक और एल्गोरिद्मिक पक्षपात जैसी चुनौतियाँ जनमत निर्माण की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं। डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध सूचनाओं की अधिकता के कारण नागरिकों के लिए सही और गलत जानकारी के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। कई बार भावनात्मक और विवादास्पद सामग्री तथ्यपरक सूचनाओं की तुलना में अधिक तेजी से प्रसारित होती है, जिससे जनमत प्रभावित हो सकता है।

भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में डिजिटल मीडिया को न तो पूर्ण रूप से सकारात्मक और न ही केवल नकारात्मक माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। यह एक ऐसा माध्यम है, जिसकी प्रभावशीलता और लोकतांत्रिक उपयोग नागरिकों, मीडिया संस्थानों, सरकार तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। यदि डिजिटल मीडिया का उपयोग जागरूकता, संवाद और सहभागिता के लिए किया जाए तो यह लोकतंत्र को अधिक मजबूत बना सकता है, लेकिन यदि इसका उपयोग गलत सूचना और विभाजनकारी विचारों के प्रसार के लिए किया जाता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती बन सकता है।

© 2006 sarvagya | All Rights Reserved
www.sarvagyajournal.com

Vol. 3, Issue 3, July-Sseptember 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22115875

SARVAGYA

ISSN (Online)
3048-7153
Vol. 3 | Issue 3
July to Sep 2026

www.sarvagyajournal.com | the.editor.org@gmail.com | Peer Reviewed & Refereed Journal

सुझाव (Recommendations)-

1. डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि नागरिक ऑनलाइन उपलब्ध सूचनाओं की विश्वसनीयता को समझ सकें और जिम्मेदारीपूर्वक डिजिटल मंचों का उपयोग कर सकें।
2. फैक्ट-चेकिंग तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि गलत सूचनाओं और दुष्प्रचार के प्रभाव को कम किया जा सके।
3. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से एल्गोरिद्म आधारित सामग्री वितरण और डेटा उपयोग के संबंध में।
4. मीडिया संस्थानों को डिजिटल नैतिकता और पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिससे विश्वसनीय और संतुलित सूचनाएँ नागरिकों तक पहुँच सकें।
5. लोकतांत्रिक संवाद को प्रोत्साहित करने वाली डिजिटल संस्कृति विकसित की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न विचारों का सम्मान और तर्कपूर्ण बहस को महत्व दिया जाए।
6. शैक्षणिक संस्थानों में मीडिया एवं डिजिटल साक्षरता से संबंधित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि युवा वर्ग डिजिटल सूचनाओं का विवेकपूर्ण उपयोग कर सके।

अंततः कहा जा सकता है कि डिजिटल मीडिया आधुनिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। यह जनमत निर्माण की प्रक्रिया को अधिक व्यापक और सहभागी बनाने की क्षमता रखता है, किंतु इसके प्रभावी उपयोग के लिए तकनीकी विकास के साथ सामाजिक जागरूकता, नैतिक जिम्मेदारी और संस्थागत उपायों की आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र में डिजिटल मीडिया की भूमिका भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित के अनुरूप विकसित करना आवश्यक है।

संदर्भ सूची (References)-

Castells, M. (2009). Communication Power. Oxford University Press.
Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962)
Lippmann, W. (1922). Public Opinion. Harcourt, Brace and Company.
McCombs, M. E. (2004). Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion. Polity Press.
McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.
Shirky, C. (2011). Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age. Penguin Books.
Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press.
Chadwick, A. (2017). The Hybrid Media System: Politics and Power (2nd ed.). Oxford University Press.
Kumar, K. J. (2020). Mass Communication in India (5th ed.). Jaico Publishing House.
Van Dijk, J. (2020). The Digital Divide. Polity Press.

© 2006 sarvagya | All Rights Reserved
www.sarvagyajournal.com

Vol. 3, Issue 3, July-Sseptember 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22115875